

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

मस्तराम

10 सितम्बर, 2004

[बी.एन. अग्रवाल और एच.के. सेमा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302- बैलिस्टिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य के आधार पर विचारणीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध- उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी करना- अपील पर माना गया, उच्च न्यायालय कानून व तथ्यों की गंभीर त्रुटि में पड गया, जिसके कारण न्याय की हानि हुई। इसलिए उच्च के आदेश को रद्द कर दिया गया और विचारणीय न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया गया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973:

धारा 293-सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के अधीन रिपोर्ट होने का दावा करने वाले दस्तावेज-उपधारा (4) में सूचीबद्ध अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेज के लेखक की परीक्षा किए बिना न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने गोली मारकर मृतक की हत्या कर दी। अभियोजन का मामला चश्मदीद गवाहों की गवाही पर,

चिकित्सा विशेषज्ञ और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर आधारित था, विचारणीय न्यायालय ने परीक्षण किया और पाया कि मृतक जिस स्थान पर खड़ा था और बंदूक की गोली से मारा गया, वह व्यक्ति फायरिंग रेंज के भीतर था। तदनुसार, विचारणीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील लगी है।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए

आयोजित- 1. हालांकि यह सच है कि आम तौर पर बंदूक की फायरिंग रेंज अलग-अलग बंदूकों में भिन्न होती है। उच्च न्यायालय की यह राय है कि डीबीएमएल बंदूक और एसबीएमएल बंदूक की फायरिंग रेंज अलग-अलग है, यह किसी विशेषज्ञ की राय पर आधारित नहीं है और यह अनुमानों पर आधारित है। मौजूदा मामले में दोनों बंदूकें एक ही श्रेणी की हैं, सिवाय इसके कि अपराध इस्तेमाल की गई बंदूक डबल बैरल की है और परीक्षण के दौरान सिंगल बैरल का उपयोग किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि डीबीएमएल बंदूक की फायरिंग रेंज एसबीएमएल बंदूक से भिन्न थी और इसके विपरीत भी। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष भ्रामक एवं विकृत है। [272-एच: 273-ए, बी.]

2. उच्च न्यायालय ने धारा 293 की उप-धारा (1) के प्रावधान को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है और एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी धारा 293 की उप-धारा (4) के तहत

सूचीबद्ध अधिकारी नहीं है। धारा 293 की उप-धारा (4) में न्यायालय को दस्तावेजों के लेखक का परीक्षण किए बिना उसमें सूचीबद्ध छह अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की परिकल्पना की गई है। [273-जी, एच]

3. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक के शरीर से बरामद छरों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजने में अभियोजन पक्ष की विफलता, अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता के खिलाफ निष्कर्ष निकालेगी, पूरी तरह से विकृत है। कानून में यह आवश्यक नहीं है कि शरीर से बरामद छरों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा जाए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि छरें प्रदर्शित बंदूक से दागे गए थे या नहीं। इसके विपरीत शरीर से छरों की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली से हुई। [274-बी, सी]

4. चश्मदीद गवाहों की स्पष्ट गवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार या चर्चा नहीं की गई है। उनकी गवाही को दुश्मनी और रिश्ते के आधार पर दहलीज पर फेंक दिया गया। यह कानून की आवश्यकता नहीं है। कानून की एकमात्र आवश्यकता उनकी गवाही पर सावधानी से विचार करना है। गवाहों का रिश्ता उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है, अन्यथा, यह आत्मविश्वास को प्रेरित करता

है। उच्च न्यायालय स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर चर्चा और विचार करने में भी विफल रहा। [276-डी, ए; 275-एच; 276-ई]

5. चश्मदीद गवाहों की गवाही चिकित्सा अधिकारी की राय से पुष्ट हुई, जिसने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने अभियोजन के मामले को संदेह से परे स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। उच्च न्यायालय द्वारा कानून और तथ्यों की गंभीर त्रुटि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई। [277-जी, एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 267/1999.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 195/1997 में निर्णय एवं आदेश की दिनांक 08.05.1998 से।

जे.एस. अत्री और एल.आर. रथ अपीलकर्ता।

ए.वी. पल्ली और श्रीमती रेखा पल्ली प्रतिवादी।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

सेमा, जे.:

एकमात्र प्रतिवादी- अभियुक्त को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), कांगड़ा धर्मशाला द्वारा आईपीसी की धारा 302 के अपराध में दोषी ठहराया गया था एवं कठोर आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का जुर्माना भरने एवं इसकी चूक में छह महीने की अवधि के लिए और कठोर

कारावास की सजा सुनाई गई। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुमति दे दी गई और विचारणीय न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया, इसलिए राज्य द्वारा यह अपील पेश की गई है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

आरोपी और अभियोजन पक्ष के गवाह सभी एक ही गांव सुग तरखाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के हैं। आबादी एवं दिवानी मुकदमे के विवाद को लेकर आरोपी और पी.डबल्यू-5 ज्ञान चंद के बीच विवाद चल रहा था और उनके बीच दीवानी मुकदमा लंबित था। मृतक उत्तम चंद दिल्ली में बढ़ई का काम करता था और दिनांक 05.08.1995 को अपनी मां की पहली बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव आया था। बताया गया है कि दिनांक 14.08.1995 को सुबह लगभग 10.00 बजे ज्ञान चंद-गवाह पी.डबल्यू-5 का आबादी के विवाद को लेकर आरोपी मस्त राम के साथ झगड़ा हुआ था और मृतक उत्तम चंद ने हस्तक्षेप किया था और ज्ञान चंद और मस्त राम दोनों को झगड़ा न करने और फैसले का इंतजार करने की सलाह दी थी। इसके बाद आरोपी मस्त राम क्रोधित हो गया और धमकी दी कि वह सबसे पहले उससे निपटेगा, क्योंकि वह ज्ञान चंद का पक्ष ले रहा था, जिसके साथ आरोपी का आबादी को लेकर दिवानी विवाद था। आगे बताया गया है कि सुबह करीब 10.30 बजे. उसी दिन, जब

मृतक उत्तम चंद अपने भाई हंस राज पी.डबल्यू-1 और विजय कुमार पी.डबल्यू-3 के साथ मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे और आरोपी के घर के सामने से गुजर रहे थे कि हाथ में डीबीएमएल (डबल बैरल मजल लोडेड) बंदूक लिए हुए आरोपी मस्त राम ने उत्तम चंद को चुनौती देते हुए कहा कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर उत्तम चंद पर गोली चला दी। मृतक उत्तम चंद के हाथ, छाती और कंधे पर चोटें आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी बंदूक लेकर खेत की ओर भाग गया। इसी बीच, पी.डबल्यू-4 तरसेम लाल भी आ गए और पी.डबल्यू 1, 3, और 4 ने मिलकर मृतक उत्तम चंद को उसके पास के घर में ले गए, जहां कुछ समय बाद उसने अंतिम सांस ली। मामले की सूचना गांव के प्रधान को दी गई, जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी और तदुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी को दिनांक 18.08.1995 को पी.डबल्यू-15 द्वारा गिरफ्तार किया गया था और एक प्रकटीकरण बयान के अनुसार, डीबीएमएल बंदूक (प्रदर्श पी-11) उसके घर के पास झाड़ियों के नीचे से बरामद की गई थी। प्रदर्श पी-11 को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था और यह काम करने की स्थिति में पाया गया और इसे निकाल दिया गया था। अभियुक्त ने धारा 313 दं.प्र.सं के तहत अपने बयान में अनभिज्ञता जताई, लेकिन उसने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। हालाँकि, घटनास्थल का निरीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं के तहत उसके परीक्षण में आरोपी के अनुरोध पर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि

धारा 313 दं.प्र.सं के तहत उसके परीक्षण में आरोपी का बचाव यह था कि उस स्थान से जहां आरोपी पर गोली चलाने का आरोप है मृतक और वह स्थान जहां मृतक खड़ा था और बंदूक की गोली से मारा गया था, फायरिंग रेंज के भीतर नहीं था। इसके चलते विचारणीय न्यायालय को मौका मुआयना करना पड़ा। विचारणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.1996 को अभियुक्त, उसके वकील और लोक अभियोजक की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया था। विचारणीय न्यायालय ने उस स्थान से बंदूक की गोली का परीक्षण किया, जहां आरोपी पर मृतक पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था और यह देखा गया कि वह स्थान जहां मृतक खड़ा था और बंदूक की गोली से मारा गया था, वह फायरिंग रेंज के भीतर था।

विचारणीय न्यायालय ने पी.डब्लू 1, 3, 4, और पी.डब्लू-2- डॉ. संजय कुमार महाजन, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था और फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला स्थापित किया और प्रतिवादी को पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय ने विचारणीय न्यायालय द्वारा दी की गई सजा को खारिज कर दिया, सबसे पहले कि जिस डीबीएमएल बंदूक (प्रदर्श पी-11) का कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया था, उसका इस्तेमाल स्थानीय निरीक्षण के समय अग्नि परीक्षण में नहीं किया गया था।

विचारणीय न्यायालय द्वारा इसके बजाय पी.डब्लू-1 हंसराज की एसबीएमएल (सिंगल बैरल मजल लोडेड) बंदूक की मदद से एक अग्नि परीक्षण किया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि इससे अभियोजन की कहानी पर वास्तविक प्रभाव पड़ा है। उच्च न्यायालय के अनुसार, फायरिंग रेंज हर बंदूक में भिन्न होती है और इसलिए, फायरिंग परीक्षण प्रदर्श पी-11 से नहीं किया गया है, विचारणीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष है कि मृतक को बंदूक की गोली से मारा गया है। मृतक के घर के बरामदे से फायरिंग रेंज के भीतर होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हमारी राय में यह निष्कर्ष न केवल भ्रामक है बल्कि विकृत भी है। जबकि यह सच है कि आम तौर पर, बंदूक की फायरिंग रेंज हर बंदूक में अलग-अलग होती है, उच्च न्यायालय की राय है कि डीबीएमएल बंदूक और एसबीएमएल बंदूक की फायरिंग रेंज अलग-अलग है, किसी विशेषज्ञ की राय पर आधारित नहीं है और यह अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। मौजूदा मामले में दोनों बंदूकें एक ही श्रेणी की हैं, सिवाय इसके कि अपराध में इस्तेमाल की गई बंदूक डबल बैरल है और परीक्षण के दौरान इस्तेमाल की गई बंदूक सिंगल बैरल है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि डीबीएमएल बंदूक की फायरिंग रेंज एसबीएमएल बंदूक से भिन्न है या इसके विपरीत।

इसके अलावा, दं.प्र.सं. की धारा 310 के तहत स्थानीय निरीक्षण की परिकल्पना की गई है। परीक्षण पहले से ही दर्ज की गई साक्ष्य का उचित



विवेचन करने के उद्देश्य से है। विचारणीय न्यायाधीश द्वारा किए गए अभिलिखित स्थल निरीक्षण के ज़ापन को पहले से अभिलिखित साक्ष्य के साथ संयोजन में सरहना की जानी चाहिए। विचारणीय न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए ज़ापन में कोई भी चूक या कमीशन अपने आप में कोई महत्वपूर्ण अनियमितता का गठन नहीं करेगा, जो अभियोजन मामले को खराब कर देगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

दूसरा, जिस आधार पर हाई कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को खारिज किया है, वह बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। बैलिस्टिक विशेषज्ञ (उदा. पी-एक्स) की रिपोर्ट पर एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैलिस्टिक) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उप-धारा (4) के तहत सूचीबद्ध अधिकारी नहीं है और इसलिए, उसकी परीक्षा के अभाव में ऐसी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा जा सकता है। हमारे विचार से उच्च न्यायालय का यह तर्क भी गलत है। सबसे पहले, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-एक्स) केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैलिस्टिक) के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत की गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि रिपोर्ट एक सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के अधीन प्रस्तुत की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(1) में यह आदेश दिया गया है कि इस धारा के तहत किसी सरकारी वैज्ञानिक

विशेषज्ञ के हाथ से रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज, किसी भी मामले या वस्तु पर उसे जांच या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किया जाए, संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने धारा 293 की उपधारा (1) के प्रावधान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी धारा 293 की उपधारा 4 के तहत सूचीबद्ध अधिकारी नहीं है। क्या धारा 293 उपधारा 4 की परिकल्पना यह है कि अदालत दस्तावेजों के लेखक की जांच किए बिना उनमें सूचीबद्ध छह अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी दस्तावेजों को वैध सबूत के रूप में स्वीकार कर सकती है।

तीसरा, उच्च न्यायालय का विचार था कि पीडब्ल्यू-2 डॉ.संजय कुमार महाजन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान, दो छर्रे बरामद किए गए थे- मृतक के दाएं और बाएं फेफड़े से एक-एक, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था। हालाँकि, बरामद किए गए छर्रों को कभी भी बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास जांच के लिए नहीं भेजा गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसे छर्रे बंदूक से दागे गए थे (उदा. पी-11) या नहीं। उच्च न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा छर्रों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजने में विफलता अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता के खिलाफ एक निष्कर्ष निकालेगी। हमारे विचार से यह

निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है। यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि शरीर से बरामद छर्रों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि छर्रें प्रदर्शित बंदूक से चलाए गए थे या नहीं। इसके विपरीत, शरीर से छर्रों की बरामदगी स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करती है कि मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई।

अभियोजन की कहानी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया चौथा कारण मृतक के शरीर पर चोट संख्या 2 गैर-स्पष्टीकरण के संबंध में है। चोट संख्या 2 का वर्णन इस प्रकार किया गया:-

"बायीं बांह की ओर बायीं कांख में लगभग 1.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।"

जिरह के दौरान पी.डबल्यू-2 डॉ. संजय कुमार महाजन ने कहा कि यदि घायल उत्तम चंद ने चलते समय अपना हाथ नहीं उठाया होता तो उपरोक्त चोट नहीं लगती। उच्च न्यायालय का विचार था कि पी.डबल्यू-1 और पी.डबल्यू-3 जो प्रासंगिक समय पर मृतक उत्तम चंद के साथ थे, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मृतक उत्तम चंद ने किसी भी समय चलते समय या चुनौती दिए जाने पर अपना हाथ उठाया था। पी.डबल्यू-1 हंस राज और पी.डबल्यू-3 विजय कुमार का स्पष्ट बयान है कि जब वे मृतक के साथ जा रहे थे, तो आरोपी ने मृतक को चुनौती दी और उसके बाद उस पर गोली चला दी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब मृतक को चुनौती दी गई तो उसने या तो बचाव में या चुनौती स्वीकार करते हुए अपने हाथ

उठाकर प्रतिक्रिया की होगी और इस प्रक्रिया में उसे चोट नंबर 2 लगी होगी, जैसा की वर्णित है। ऐसी परिस्थितियों में हाथ उठाने पर मृतक की प्रतिक्रिया, सामान्य परिस्थितियों में प्राकृतिक मानव व्यवहार के अनुरूप और सुसंगत होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अप्रत्याशित होती है। हर कोई अपने तरीके से प्रतिक्रिया देता है। ऐसे प्राकृतिक मानव व्यवहार को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना कठिन है। प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी विवेचना की जानी चाहिए।

पांचवा, उच्च न्यायालय का यह भी मानना था कि पीडब्ल्यू-1 हंस राज और पीडब्ल्यू-3 विजय कुमार मृतक के साथ थे और अभियोजन पक्ष की कहानी से पता चलता है कि बंदूक की गोली से छर्रे बिखर गए थे और यहाँ तक कि पेड पर भी लगे थे, लेकिन पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-3 पर चोटों की अनुपस्थिति उनकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाती है। हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष, भी भ्रामक एवं विकृत है। पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-3 ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक उनके आगे चल रहा था। आरोपी ने निर्विवाद रूप से पी.डब्ल्यू-5 ज्ञान चंद का पक्ष लेने पर मृतक के प्रति द्वेष पाल रखा था, जिसके साथ अभियुक्त का दिवानी विवाद था, उसने मृतक को चुनौती दी, बंदूक का निशाना बनाया और उस पर

गोली चला दी। इन परिस्थितियों में, पी.डबल्यू-1 और पी.डबल्यू-3 के उपर गोली की चोटों का अभाव होने से पी.डबल्यू-1 और पी.डबल्यू-3 की उपस्थिति को संदिग्ध बनाने का कोई आधार नहीं है।

उच्च न्यायालय का आखिरी और सबसे विकृत और भ्रामक निष्कर्ष चश्मदीद गवाहों पी.डबल्यू-1 हंस राज और पी.डबल्यू-3 विजय कुमार की साक्ष्य को खारिज करने के संबंध में है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष को निम्नानुसार दर्ज किया: -

‘पी.डबल्यू-1 हंस राज मृतक का सगा भाई है, जबकि पी.डबल्यू-3, विजय कुमार, मृतक का चचेरा भाई होने के अलावा, पी.डबल्यू-5, ज्ञान चंद का बेटा है, जिसके साथ आरोपी का मुकदमा चल रहा था। यह अभियोजन पक्ष का अपना मामला है कि अभियुक्त मृतक और पी.डबल्यू-1 के प्रति द्वेष रखता था, क्योंकि वे पी.डबल्यू-5, ज्ञान चंद की मदद कर रहे थे और उसका पक्ष ले रहे थे। इसलिए, पी.डबल्यू-1 और पी.डबल्यू-3 दोनों ही हितबद्ध गवाह हैं और रिकॉर्ड पर आने वाले साक्ष्यों को देखते हुए, उन पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है।’

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि पी.डबल्यू-1 हंस राज और पी.डबल्यू-3 विजय कुमार दो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक के साथ थे। दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए खेतों में जाते समय वे मृतक के साथ थे। जब वे आरोपी के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो आरोपी ने मृतक को ललकारा

और इसी बीच उस पर गोली चला दी, जिससे मृतक उत्तम चंद गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों चश्मदीदों से लंबी जिरह की गई लेकिन उनकी गवाही की विश्वसनीयता पर संदेह करने वाली कोई बात सामने नहीं आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-3 रिश्तेदार हैं, लेकिन यह उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं होगा, यदि अन्यथा, विश्वास को प्रेरित करता है। इस मुद्दे पर कानून सुस्थापित है कि रिश्ते के आधार पर रिश्तेदार गवाह की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एकमात्र आवश्यकता उनकी गवाही की सावधानी से परीक्षण करना है। मामले के दिए गए तथ्यों में, यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि रिश्तेदार मृतक के साथ उस दिन सुबह लगभग 10.30 बजे खेतों से मवेशियों के लिए चारा लेने गए होंगे। अभियोजन साक्ष्य में यह भी है कि सुबह 10.30 बजे की घटना से पहले उसी दिन सुबह लगभग 10.00 बजे आरोपी मस्त राम और पीडब्ल्यू-5 ज्ञान चंद के बीच विवादित आबादी को लेकर विवाद और झगड़ा हुआ और मृतक उत्तम चंद ने मामले में हस्तक्षेप किया और पीडब्ल्यू-5 ज्ञान चंद और आरोपी मस्तराम दोनों को झगड़ा न करने और दिवानी मुकदमे के फैसले की प्रतीक्षा करने की सलाह दी। साक्ष्यों में यह भी है कि इसके बाद आरोपी मस्त राम ने मृतक उत्तम चंद को धमकी दी कि वह सबसे पहले उससे निपटेगा, क्योंकि वह ज्ञान चंद का पक्ष ले रहा है जिसके साथ आरोपी का आबादी के संबंध में मुकदमा चल रहा है। चश्मदीद गवाहों की स्पष्ट गवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार या चर्चा नहीं की गई है। उनकी गवाही को दुश्मनी

और रिश्ते के आधार पर दहलीज पर फेंक दिया गया। यह कानून की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पीडब्ल्यू-4 तरसेम लाल एक स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी है। पीडब्ल्यू-4 भी उसी गांव का रहने वाला है। उनका न तो शिकायतकर्ता पक्ष से संबंध है और न ही आरोपी पक्ष से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोपी मस्तराम को अपने बरामदे में हाथ में गमछा लिए देखा था और गोलीबारी के बाद उसे मौके से भागते हुए भी देखा था। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यू-4 की गवाही पर बिल्कुल भी विचार या चर्चा नहीं की है।

पीडब्ल्यू 1, 3 और 4 की गवाही बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और पीडब्ल्यू-2 डॉ. संजय कुमार महाजन के साक्ष्य के अनुरूप थी, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

1. एक्रोमियन से लगभग 9 इंच की दूरी पर बायीं भुजा की अग्र-पार्श्व सतह पर लगभग 1 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।
2. बायीं कांख में बाएं हाथ की ओर लगभग 1.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।
3. बायें कंधे के सामने की सतह पर लगभग 1 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।
4. चोट संख्या 3 से लगभग 3 सेमी. नीचे 1.2 सेमी व्यास वाला गोलाकार क्षेत्र।

5. बायीं कांख की मध्य दीवार पर 1.3 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र, जो छाती की दीवार से बनता है। जांच करने पर ट्रैक्ट बन गया है:-3 इंच अंदर जांच में पाया गया।
6. मध्य क्लैविकुलर बिंदु से 7 सेमी नीचे बाएं इन्फ्रा क्लैविक्युलर क्षेत्र में लगभग 1.4 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।
7. चोट क्रमांक 6 से लगभग 2.3 सेमी नीचे 1.2 सेमी व्यास वाला एक गोलाकार क्षेत्र।
8. बाएं निपल से लगभग 2 सेमी दूर मध्य-उपरी भाग का एक क्षेत्र 2 सेमी गुणा 1 सेमी।
9. उरोस्थि पर 3.2 सेमी गुणा 2.3 सेमी का क्षेत्र, उरोस्थि पायदान से लगभग 5 सेमी नीचे।
10. जिफी स्टनम के लगभग 5 सेमी दूर बाएं तटीय मार्जिन के ऊपर 4.1 सेमी गुणा 2.3 सेमी का क्षेत्र।
11. उरोस्थि के दाहिनी ओर 1 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र।
12. मध्य हंसली बिंदु से लगभग 10 सेमी नीचे छाती के दाहिनी ओर 7.2 सेमी गुणा 2.1 सेमी का क्षेत्रफल, केंद्र में सबसे चौड़ा, परिधि पर पतला।
13. दाहिनी हंसली के मध्य सिरे से लगभग 13 सेमी 6.5 सेमी गुणा 3.1 सेमी का क्षेत्रफल।



14. दाहिने निपल के ठीक नीचे 15 सेमी व्यास का एक क्षेत्र।

जांच करने पर:- नंबर 13, यह सबक्यूटेनिक्स प्लानर के माध्यम से चोट नंबर 14 से बाहर आया।”

पी.डबल्यू-2 डॉ. संजय कुमार महाजन की राय है कि सभी चोटें बंदूक जैसी आग्नेयास्त्र से लगी थीं और ऐसी चोटें मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त थीं।

हमारे विचार में, पी.डबल्यू 1, 3 और 4 की सुसंगत चश्मदीद गवाहों, पी.डबल्यू-2 डॉ. संजय कुमार महाजन की राय और बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से सभी उचित संदेहों से परे अभियोजन मामले को स्थापित किया और उच्च न्यायालय कानून व तथ्यों की गंभीर त्रुटि में पड़ गया, जिसके कारण न्याय की हानि हुई।

उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और विचारणीय न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी अभियुक्त मस्तराम का जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है। उसे तुरंत हिरासत में वापस लेने का निर्देश दिया गया है। आज से एक माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट।

के.जी

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यशवंत आमेरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।